



मनरेगा के
15 वर्ष

14
रिपोर्ट्स,

बदलाव **16,000**
की कहानी **किलोमीटर**
की यात्रा,

साल 2006 में पहली बार जिन जिलों में मनरेगा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम (मनरेगा) लागू हुआ, वे जल संरक्षण
की कसौटी पर कितने खरे उतरे?

16 गांव
15 राज्य



पड़ताल क्यों जरूरी है? क्योंकि

मनरेगा सिर्फ शारीरिक श्रम वाले रोजगार का
सृजन भर नहीं करता

कानून में कहा गया है कि इसके 60 प्रतिशत कार्य जल से
संबंधित संरचनाओं से जुड़े होंगे

पिछले 15 वर्षों में 3 करोड़ जल संरक्षण संबंधी काम हुए हैं।
यानी हर गांव में 50 जल संरक्षण के काम हुए हैं

इन संरचनाओं की मदद से हम 15 वर्षों में 28,741 मिलियन
क्यूबिक मीटर पानी बचा पाए हैं



हम जानते हैं कि पानी ही हमारे वर्तमान और भविष्य का **निर्धारक** है

लेकिन **जलवायु परिवर्तन तापमान को बढ़ा रहा है**, वर्षा की प्रवृत्ति को बदल रहा है। ऐसे स्थिति में हमें जल प्रबंधन ही बचा सकता है

हमारी **आजीविका की सुरक्षा** के लिए पानी की सुरक्षा सबसे अहम है

इससे हम मौसम के कोपभाजन से काफी हद तक **बच सकते हैं**

मनरेगा **दुनिया का सबसे बड़ा** सामाजिक सुरक्षा और जलवायु जोखिम को कम करने वाला कार्यक्रम है

लेकिन **यह कितना असरदार है?** यह पता लगाने के लिए हमने इस कार्यक्रम की गहन पड़ताल की



बंदलापल्ली गांव

अनंतपुर, आंध्र प्रदेश

“हमारा गांव सूखे के अभिशाप से मुक्त हो चुका है”

यह देश का पहला गांव है जहां मनरेगा की शुरुआत हुई

2006

लगातार सूखे और पलायन से जूझ रहे इस गांव में मरुस्थल विकास कार्यक्रम के माध्यम से इन समस्याओं से निपटा गया

2021

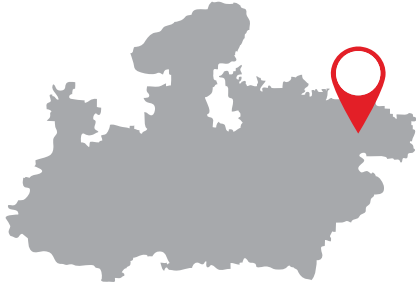
900 जल संरचनाएं बनकर तैयार हो गईं

अब यह गांव सूखे से बचाव के लिए तैयार है

2018-2019 में जब जिले में 100 साल की सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई तब भी यह सूखे से प्रभावित नहीं हुआ

**गांव के लोगों को नगदी फसलें मिल रही हैं,
डेरी का काम बढ़ा है और पलायन भी थम गया है**

**गांव ने मनरेगा के फंड को पानी की सुरक्षा में निवेश किया
और अपनी आजीविका को सुरक्षित कर लिया**



बरमानी

सीधी जिला, मध्य प्रदेश

“अब हमारे पास अतिरिक्त खाद्य है”

2006

मैं जब डाउन टू अर्थ पहली बार गांव में दौरे के लिए पहुंचा तो
यह उजाड़ और संकटग्रस्त था

उस वक्त गांव में मनरेगा के तहत जलसुरक्षा पर निवेश किया गया

2021

मैं डाउन टू अर्थ ने फिर इस गांव का दौरा किया
7 बड़े तालाब, 39 कुएं ठीक किए गए जिनसे पूरे साल पानी रहता है

गांव के सभी निवासी स्थापित किसान हैं
और पूरे वर्ष में 10 महीने खेती करते हैं

महिलाओं को पानी लाने के लिए
समय नहीं बर्बाद करना पड़ता

गांव अपनी पांचवर्षीय योजना
में पानी को प्राथमिकता देता है



पुकुटुकावू

पलक्कड जिला, केरल

“महिलाओं ने पुनर्जीवित की नदी”

2006

साल में 2300 मिलीमीटर वर्षा के बाद
भी जल संकट की स्थिति

2021

यहां कुएं खोदने वाला भारत का सबसे बड़ा महिला समूह है।
गांव में 200 कुएं खोदने की योजना

सैकड़ों जल संचयन संरचनाएं
भूजल को रीचार्ज कर रही हैं

सूख चुकी जल धाराएं
फिर से फूट पड़ी हैं

महिलाओं ने
अगुवाई की



हिम्मतपुरा

जालौन जिला, उत्तर प्रदेश

“आय में 10 गुणा बढ़ोतरी”

2006

सिर्फ एक चेकडैम था

2021

तीन कुंओं में पानी आया,
80 प्रतिशत ग्रामीणों की प्यास बुझी

शहरों में पलायन कर चुके

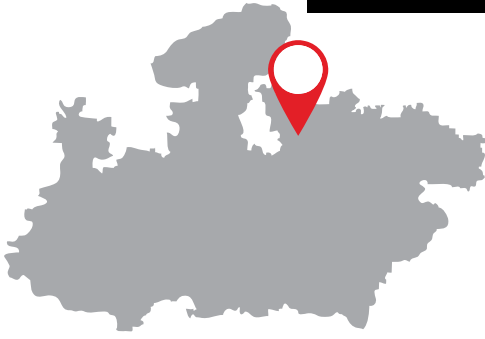
ग्रामीण वापस लौटे

वर्षा जल पर निर्भरता खत्म हुई है

क्योंकि पर्याप्त पानी का संचय किया गया

70 प्रतिशत खेत सिंचित हुए,

आय में 10 गुणा तक बढ़ोतरी हुई



नादिया

टीकमगढ़ जिला, मध्य प्रदेश

“55 टैंक का जाल”

2006

केवल 30 फीसदी जमीन पर खेती, 45 वर्षों में
40 सूखे पड़े। गांव में डाउन टू अर्थ पहुंचा

2021

55 तलैयाओं का निर्माण किया गया

हर तलैया से 4 हेक्टेयर

भूमि सिंचित की जाती है

90 फीसदी खेत

सिंचित हो रहे हैं

आय में 400 फीसदी

की बढ़ोतरी हुई है



भुआंपाडा

बालांगीर जिला, उड़ीसा

“पूरे वर्ष रोजगार”

2006

भारत में सबसे ज्यादा पलायन वाली जगहों में एक,
लगातार सूखे का प्रकोप

2021

5,000 खेत तालाब और बहुउद्देशीय तालाब बनाने का लक्ष्य

स्थानीय लोग सामुदायिक तालाब के लिए

अपनी जमीनें दान कर रहे हैं

भू-जल का स्तर ठीक करने के लिए

कुएं खोदे जा रहे हैं

महामारी के समय गांव लौटने वाले अधिकांश

श्रमिकों को रोजगार मिला



वेल्लापलम

नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु

“सुनामी के बाद दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए मनरेगा फंड का इस्तेमाल”

2006

सुनामी (2004) के चलते जमीन में खारा पानी भरने से उर्वराशक्ति क्षीण हुई

2021

तालाबों से गाद निकाली गई ताकि खेतों को कृषि योग्य बनाया जा सके

गांव के पुरुष पलायन कर गए थे,
घर में महिलाएं थीं

मनरेगा का साथ मिला तो महिलाओं ने तालाबों
को ठीक करने का बीड़ा उठाया

भू-जल स्तर सुधरा,
लोग फिर से खेती करने लगे



इनागारिया

पाकुड़ जिला, झारखंड

“खेती में फसलों में
चार गुणा बढ़ोतरी”

2006

5 तालाबों और 12 चेकडैम दो वर्षों में बनाने का काम शुरू हुआ था

2021

भू-जल स्तर में सुधार, खेती में चार गुणा फसल में बढ़ोतरी

तालाबों का रखरखाव

और समुदाय द्वारा चेकडैम को दुरुस्त किया गया

गांव अब किसी तरह की

सरकारी सहायता नहीं ले रहा है

जो इन स्रोतों का पानी इस्तेमाल करता है,

वह इन्हें ठीक रखने के लिए श्रम भी करता है



बीरबन्ध

बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल

“समृद्धि का 30x40 मॉडल”

2006

चट्टानी सतह के कारण वर्षा का पानी तत्काल बह जाता था

2021

अब तक 25 वर्षा जल संचयन वाली संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं

यह वर्षा जल संचयन का

30x40 मॉडल है

30 मीटर नीचे एक ढलान से वर्षा जल

40 मीटर के क्षैतिज टैंक में चला जाता है

2018-2020 में भू-जलस्तर

में 1.7 मीटर की बढ़ोतरी हुई है



बटकाफाला

डूंगरपुर जिला, राजस्थान

“सूखा और बाढ़ दोनों से बचाव”

2006

सूखा और पलायन के लिए बदनाम

2021

वर्षा जल से रीचार्ज के लिए बड़े पैमाने पर पहाड़ी ढाल पर ट्रेंचेस बनाए गए

ओवरफ्लो होने वाला पानी नदी पर बनाए गए

मसूनरी चेकडैम में एकत्र होता है

भू-जल स्तर में 15 मीटर की

बढ़ोतरी हुई

यह डैम गांव में अचानक आने वाली बाढ़

से भी लोगों का बचाव करता है



रामदुर्गा

चित्रादुर्गा जिलो, कर्नाटक

“पशुधन अर्थव्यवस्था में जान आई”

2006

देश के कुछ चुनिंदा सूखाग्रस्त जिलों में शामिल था,
जहां भू-जल स्तर 200 मीटर नीचे था

2021

पहले सामुदायिक तालाब बना, इस वक्त खेतों में तालाब जैसे निजी
संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित है

पशुओं पर आधारित आजीविका वाले इस गांव ने
बकरियों के लिए सबसे पहले सामुदायिक तालाब बनाया

इस तालाब से बकरियों के लिए
चारा और पानी सुनिश्चित हुआ, गांव के एक निवासी ने महामारी के
दौरान 50 बकरियां बेचकर 4 लाख रुपए कमाए

गांव के लोगों ने आय बढ़ाने के लिए
अब बागवानी की तरफ ध्यान देना शुरू किया है



बारोखान सिरसा जिला, हरियाणा

“मनरेगा ने किया उत्थान”

2006

मनरेगा का फायदा लेने वाले बहुत कम थे

2021

मजदूरों के द्वारा गंदे पानी को कृषि में दोबारा इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई

तालाबों के त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण हुआ

जिससे रसोई और स्नानघर से निकलने वाले पानी को ट्रीट किया जा सके

सिंचाई में पानी

का इस्तेमाल हुआ

पानी की 66 प्रतिशत बर्बादी रुकी

और भूमिगत जल पर निर्भरता कम हुई



जामुनवान

कैमूर जिला, बिहार

“मगध साम्राज्य की याद को जिंदा किया”

2006

मिट्टी के बांधों का काम शुरू किया गया लेकिन ये टिकाऊ नहीं रहे

2021

पुरातन जल व्यवस्था आहर-पाइन को सिंचाई के लिए शुरू किया

गांव में कई किलोमीटर लंबी

सिंचाई चैनल है

सूखे में भी इसमें

पानी रहता है

वर्तमान में 40 फीसदी गांव

के खेत सिंचित हैं



तुपेवाड़ी

जालना, महाराष्ट्र

“एक गांव जो दो रोजगार गारंटी योजनाओं का गवाह बना”

2006

गांव राज्य की रोजगार गारंटी योजना के दायरे में था

2021

मनरेगा ने गांव की जल पूंजी को बढ़ाने में बड़ी मदद की

खेतों में कंपार्टमेंटल जुड़ाव

कुएं वर्षा जल से भरते हैं

ग्रामसभा मनरेगा मजदूरों के इस्तेमाल

की योजना बनाती है

कृषि से आय में 300

फीसदी की बढ़ोतरी हुई



मंचल

रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना

“समतलीकरण से पुनर्जीवन”

2006

ऊबड़खाबड़ जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिए
समतलीकरण कार्य हुआ

2021

400 किसानों ने अपनी जमीन का समतलीकरण करवाया

शुरुआती सालों में 2 हेक्टेयर से कम जोत
वाले खेतों का समतलीकरण हुआ ताकि खेती की जा सके

किसानों ने खेतों की मेड़ों पर टीक के पेड़ लगाए
ताकि भविष्य में आर्थिक लाभ हो

सिंचित क्षेत्र में
दोगुने से अधिक वृद्धि हुई



वासना

साबरकांठा जिला, गुजरात

“पलायन 40 प्रतिशत तक रुका”

2006

छोटे बांधों और तालाबों से शुरुआत हुई

2021

इन बांधों की मदद से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई

पहले यह पूरी तरह

वर्षा पर आश्रित था

नए तालाब 10 महीने तक

सतह का जल सुनिश्चित करते हैं

कृषि फिर से मुख्य व्यवसाय बन गई है,

सालाना बचत 2 लाख तक बढ़ी है



ये गांव क्या सीख देते हैं?

सूखा राहत से ज्यादा सूखे से बचाव

आर्थिक तरक्की का रास्ता जल संरक्षण से होकर गुजरता है

जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है, इसमें न्यूनतम निवेश चाहिए

लेकिन इसके लिए सामुदाय की भागीदारी जरूरी है, लोगों को इसमें सहयोग करना ही होगा

इन गांवों में रोजगार महत्वपूर्ण है लेकिन बदलाव पारिस्थितिकी में निवेश से आता है



मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा अनुकूलन कार्यक्रम है

जलवायु परिवर्तन से मौसम की मार बढ़ेगी

अधिक या कम बारिश होगी

जल सुरक्षा के लिए सभी का सहयोग जरूरी है

पारिस्थितिक परिसंपत्तियों के निर्माण में मनरेगा
का श्रम लगता है

इससे क्षमता विकसित होती है, गांव में इसका सही
इस्तेमाल जरूरी है

आजीविका की सुरक्षा के लिए जल संरक्षण
के प्रयास कारगर हो सकते हैं



पानी से आर्थिक अवसर सुनिश्चित करता है

हर तालाब एक आर्थिक अवसर है

हर गांव ने दिखाया है कि पलायन कैसे
रोका जा सकता है

और संपन्नता व कल्याण कैसे सुनिश्चित किया जा
सकता है यह जल संरक्षण का मौका है



मनरेगा

काम के संख्या की गणना
महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण
है कि ये काम टिकाऊ हों

हमने इन गांवों को किसी
सरकारी रिकॉर्ड में नहीं पाया

मनरेगा में अब भी निर्मित
परिसंपत्तियों की गणना होती है

लेकिन किए गए काम की
निगरानी और उसका असर
देखना अधिक जरूरी है

जल संरक्षण और गांव की
आमदनी की गणना जरूरी है

टिकाऊ परिसंपत्तियों की
जरूरत है, ग्रामीण स्तर पर
समुदायों द्वारा भागीदारी
जरूरी है

जब तक गांव के लोग खुद
आगे नहीं आएंगे, तब तक यह
कारगर साबित नहीं होगी



क्या है जल सुरक्षा?

लोकतंत्र की मजबूती

बारिश की हर बूंद को संजोना

वर्षाजल की अहमियत जानना

आजीविका को मजबूत बनाना, भविष्य का निर्माण

विश्व
जल
दिवस
2021



वर्षाजल संजोने वाले बदलाव के वाहक हैं

